भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1997

(जिसका उत्तर मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी ढांचे को सरल बनाना"

1997. **श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर स्लैब की संख्या कम करने के उपायों, छूट हटाने की योजनाओं और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों सहित माल और सेवा कर (जीएसटी) ढांचे को सरल बनाने के लिए लंबित प्रस्ताव क्या हैं; और

(ख) वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को विस्तारित करने, डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विकास करने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) : जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मंत्रियों के समूह के लिए विचारार्थ विषयों में शामिल हैं :

(i) कर आधार का विस्तार करने और आईटीसी श्रृंखला के विभाजन को रोकने के उद्देश्य से जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की समीक्षा करना;

(ii) मौजूदा कर स्लैब दरों की समीक्षा करना और आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए उनमें बदलाव की सिफारिश करना;

(iii) विशेष दरों सहित जीएसटी की वर्तमान दर स्लैब संरचना की समीक्षा करना और जीएसटी में सरल दर संरचना के लिए आवश्यक कर दर स्लैब के विलय सहित युक्तिसंगत बनाने के उपायों की सिफारिश करना।

मंत्रिसमूह ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर जीएसटी परिषद ने अपनी 47वीं बैठक में विचार किया।

मंत्रिसमूह की कोई भी रिपोर्ट वर्तमान में परिषद के विचारार्थ लंबित नहीं है।

(ख) : देश के सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप, नामतः जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप लॉन्च किया है।

सरकार का प्रयास देश के सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बैंकों द्वारा जेडीडी ऐप पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, 28.02.2025 तक देश के कुल 6,01,328 बसे हुए गांवों में से 6,00,720 (99.90%) गांव 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर किए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 16.10.2022 को हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष (आज़ादी का अमृत महोत्सव) के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग एकक (डीबीयू) समर्पित किए हैं।

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को तेज़ और व्यापक बनाने के साथ-साथ डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार लाने के उद्देश्य से डीबीयू की शुरुआत की गई है। जनवरी 2025 तक, देश भर में 107 डीबीयू स्थापित किए जा चुके हैं।

****